भारत के व्यापारिक साझेदार से ज्यादा हैं आसियान देश



हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मनीला में सम्पन्न आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उनका यह दौरा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। भारत के लिए यह बैठक कई अर्थों में महत्व रखती है।

कुछ बिंदु -

- आसियान देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों में संतुलन बनाने की बहुत जरूरत है। निःसंदेह भारत का निर्यात दोगुना हुआ है, वहीं आसियान देशों से भारत का आयात लगभग चार गुना बढ़ गया है। इसे संतुलित करने की जरूरत है।

- आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को वस्तुओं के व्यापार से आगे सेवाओं, डिजिटल तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग तक विस्तार देने की जरूरत है।

- यह साउथ एशियन फ्री ट्रेड या साफ्टा के तहत दक्षिण एशिया को एक मजबूत क्षेत्रीय व्यापारिक समूह बनाना था।

- दक्षिण-पूर्व एशिया चीन के लिए आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन की मजबूत विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला, निवेश और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के कारण इस क्षेत्र में उसका प्रभाव काफी

अधिक है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह आसियान देशों के साथ ऐसे संबंध विकसित करे, ताकि इस क्षेत्र में किसी एक देश का वर्चस्व न हो।

भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत के विस्तृत क्षेत्र के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध मजबूत किए हैं। इसी कड़ी में भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की शुरुआत की गई थी। भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली इस नीति को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

'द इकोनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 18/11/2026